हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 14 फ़रवरी 2026, समय 1305 (5 मिनट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस अड्डे से पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत नई इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअल रूप से झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ में मौजूद हैं।पीएम ई-बस सेवा योजना अगस्त 2023 में शुरू की गयी थी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल द्वारा 169 शहरों में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य तय किया गया था।

केंद्र सरकार ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने तथा उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के साथ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य का व्यापक आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात से घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी, बाजार में तरलता बढ़ेगी, कुशल स्टॉक रोटेशन सुनिश्चित होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा और संसद के नियमों का निरादर करने का आरोप

लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने दावा किया कि श्री गांधी देश की राजनीति को नहीं समझते हैं।

हरियाणा सरकार ने सुरक्षा सेवा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन और कर्मचारी डेटा से जुड़ी समस्याओं के तत्काल और समयबद्ध समाधान करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र अनुबंध कर्मचारियों का अद्यतन और सटीक डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा खजाना एवं लेखा विभाग के डेटाबेस में सुनिश्चित करें, ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले 30 जनवरी को भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब भी कई विभागों और अनुबंध कर्मचारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा 15 अगस्त, 2024 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। जांच में पाया गया कि ओटीपी जनरेशन में बाधा के प्रमुख कारणों में गलत या बदला हुआ मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र में त्रुटि तथा वेतन या मानदेय का संविदा मद के बजाय अन्य मद से भुगतान शामिल हैं।
प्रमाणित सूचना प्राप्त होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापित डेटा हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन को भेजेंगे, ताकि ओटीपी प्रक्रिया सक्षम हो सके और पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

कल चंडीगढ़ के किसान भवन में विभिन्न मंडी बोर्डों, अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों से कृषि मंडीकरण नीति के लिए मांगे गए सुझावों संबंधी अंतिम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स- कौसांब और पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसट ने कहा है कि मंडी प्रणाली को मजबूत करना और किसानों की आमदन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मंडियों में खाद्यान्न की बर्बादी न होने देना और उन्हें उपभोक्ताओं तक बेहतर ढंग से पहुंचाना जरूरी है, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सुझाव देने के लिए विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श कर एक मसौदा तैयार किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने राज्य में 31 मार्च, 2027 तक 2 लाख 22 हजार घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है।